



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 164]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1979/चैत्र 26, 1901

No. 164]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1979/CHAITRA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paglog is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1979

का. आ. 208(अ)/18चख./आई. डी. आर. ए./
79.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 277 (अ)/18-चख./आई. डी. आर. ए./78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 (जिसमें इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) की खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचादों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों से उद्भूत या प्रोद्भूत सभी बाध्यताओं और दायित्वों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनके मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की, (1) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी, (3) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (4) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, (5) मेसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, और (6) मेसर्स रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली नामक उपक्रम, पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक

उपक्रमों को लागू हो सकती हैं, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वावधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वावधि 20 अप्रैल, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है।

[फा. सं. 10/14/78 सी. एस. एम.]

आर. रामकृष्णा, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th April, 1979

S.O. 208(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E)/18FB/IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section

18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force, immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertakings known as : (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s. Udaipur Cotton Mills, Udaipur, and (vi) M/s. Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur are parties or which may be applicable to such indus-

trial undertakings shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 20th April, 1980.

[File No. 10/14/78-CSM]
R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.